भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार ...

Model Answer Key

Date : 07/07/2019

A - राष्ट्रीय आय की गणना विधि–

– उत्पादन संगणना विधि। वस्तु व सेवा प्रवाह नीति
– आय प्राप्ति विधि। आय संगणना विधि
– उपभोग बचत रीति। व्यय संगणना विधि
– सामाजिक लेखांकन

B - सी. एस. ओ क्या हैं।

भारत में राष्ट्रीय आय और संबंधित सभी पक्षों की गणना, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है।
– इसकी स्थापना– 2 मई 1951 में की गई।
– मुख्यालय– नई दिल्ली में हैं।
– CSO अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जारी करता है।

C - बहुआयामी गरीबी–

– वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया।
– बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले तीन आयाम लिये गये हैं–
1. स्वास्थ्य 2. शिक्षा 3. जीवन स्तर
– वैश्विक बहुआयमी गरीबी सूचकांक 2018 के अनुसार भारत में गरीबी दर 55 प्रतिशत से घटकर 27.5 प्रतिशत हो गई है।

D - सी. रंगराजन समिति

– योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी. रंगराजन की अध यक्षता में समिति का गठन किया।
– समिति द्वारा 2014 में अपनी रिपोर्ट सौपी गई।
– समिति के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रूपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया।

A- National Income calculation.

National income measures the monetary value of the flow of output of goods and services produced in an economy over a period of time.
Measuring the level and rate of growth of national income is important for keeping track of:
1.The rate of economic growth
2.Changes to living standards
3.Changes to the distribution of income between groups within the population.

B- What is CSO

The Central Statistics Office (CSO) is a governmental agency in India under the Ministry of Statistics and Programme Implementation responsible for coordination of statistical activities in India, and evolving and maintaining statistical standards. It has a well-equipped Graphical Unit. The CSO is located in Delhi. It was established on May 2,1951.

C- Multidimensional poverty

The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) was developed in 2010 by the Oxford Poverty & Human Development Initiative and the United Nations Development Programme.
The index uses the same three dimensions as the Human Development Index: health, education, and standard of living.
These are measured using ten indicators. Poors fall under at least 33% of indicators are called Multidimensional poors.

D- C Rangarajan Committee

Brushing aside the Tendulkar Committee report on poverty estimation, a Committee headed by former RBI governor C Rangarajan has said that the number of poor in India was much higher in 2011-12 at 29.5% of the population.Persons spending below Rs. 47 a day in cities & Rs. 32/day in villages should be considered poor. It was formed in 2013.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

E- बेरोजगारी दर :–

बेरोजगारी दर से अभिप्राय श्रम बल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कुल बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या से है?

$$\text{बेरोजगारी दर} = \frac{\text{रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

F- प्रधानमंत्री उज्जवल योजना–

मई 2016 में केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बी.पी.एल) परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एल. पी. जी. कलेक्शन प्रदान किये गये।

– योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल परिवारों को 2019 तक 5 करोड़ एल.पी.जी. कलेक्शन प्रदान करने के लिए रूपये 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– बी.पी.एल. परिवारा को LPG कनेक्शन के लिए 1600 रूपयें की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

G- UBI (यूनिवर्सल बेसिक इनकम)

– यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है, जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी।
– इसके लिए व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा।

H- अल्पविकसित अर्थव्यवस्था–

जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का सतर काफी नीचा होता हैं, उसे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं।

– विश्व बैंक के अनुसार जिनकी प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 995 डॉलर या इससे कम है।
– जैसे चाड़ नाइजर सोमालिया आदि।

I- न्यूनतम समर्थन मूल्य–

– वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है।
– भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में दो बार, फसल बोने से पहले करती हैं।

E- Unemployment Rate

Unemployment rate is the number of unemployed people as a percentage of the labour force, where the latter consists of the unemployed plus those in paid or self-employment. Unemployed people are those who report that they are without work, that they are available for work and that they have taken active steps to find work in the last four weeks.

In June 2019, India's unemployment rate is 6%.

F- Pradhanmantri Ujjawalla Yojna

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) was launched by Prime Minister of India Narendra Modi on 1 May 2016 to distribute 50 million LPG connections to women of BPL families.
A budgetary allocation of ₹ 800 billion.
In 2018 Union Budget of India, its scope was widened to include 80 million poor households of which half are SC ST families.

G- Universal Basic Income

Universal Basic Income (UBI) is a form of social security that guarantees a certain amount of money to every citizen within a given governed population, without having to pass a test or fulfill a work requirement.
The purpose of the UBI is to prevent or reduce poverty, increase equality among citizens & reduce corruption.This concept believes in people's discretion.

H- Underdeveloped economy

The term underdevelopment refers to that state of an economy where levels of living of masses are extremely low due to very low levels of per capita income resulting from low levels of productivity and high growth rates of population.

I- Minimum Support Price

Minimum Support Price (MSP) is a form of market intervention by the Government of India to insure agricultural producers against any sharp fall in farm prices.
The minimum support prices are announced by the Government of India on the basis of the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए गेहूँ हेतु MSP 1840 रूपयें निर्धारित किया गया।

The minimum support prices are a guaranteed price for their produce from the Government. The major objectives are to support the farmers from distress sales and to procure food grains for public distribution.

J - मेगाफूड पार्क–

वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई।

– अब तक कुल 42 मेगा फूड पार्क को केन्द्र की मंजूरी मिल चुकी है।

– मेगा फूड पार्क स्कीक 'क्लस्टर' दृष्टिकोण पर आधारित है।

J- Mega food park

Mega Food Park is a scheme of the Ministry of Food Processing (part of the Government of India) with the aim of establishing a "direct linkage from farm to processing and then to consumer markets" through a network of collection centres and primary processing centres.

Its purpose was to increase processing of perishables from 6% to 20% and to increase India's share in global food trade by at least 3% up to year 2015

A total of 42 Mega Food Parks have been sanctioned so far.

K - विश्वेश्वरैया योजना–

– भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित 'Planmed Economy of India' नामक पुस्तक में दिया गया।

– यह 10 वर्षीय योजना थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य – राष्ट्रीय को दुगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना।

K- Vishveshvariya Yojna

- The proposal for the first framework of economic planning in India was given in the year 1934 in the book "Economy of India" written by Vishwaswarya.

- This was a 10 year plan, whose main purpose - doubling the national, increasing the industrial production.

L - बाहरवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य–

– तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास

– पर्यावरण का संरक्षण

– सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत वृद्धि।

L- Main Objective of 12th five year Plan

Twelfth Five Year Plan focuses on Growth – Growth which is

1.Faster

2.Inclusive

3.Sustainable

M - खाद्य सुरक्षा की परिभाषा–

''सभी व्यक्तियों के लिए हर समय सक्रिय व स्वस्थ्य जीवन के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि ही खाद्य सुरक्षा होती हैं।''

''सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूपों में खाद्यान्नों की सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है।''

M- Definition of food Security

Food security is a measure of the availability of food and individuals' accessibility to it, where accessibility includes affordability.

Food security can be measured by calorie intake per person per day, available on a household budget.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

N - मुद्रा स्फीति–

अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है अर्थात् वस्तुओं –सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है जिससे कीमतें बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, 'जिसे मुद्रा स्फीति' कहते हैं।

N- Money inflation

Monetary inflation is a sustained increase in the money supply of a country (or currency area). Depending on many factors, especially public expectations, the fundamental state and development of the economy, and the transmission mechanism, it is likely to result in price inflation.

O - रेपो दर

– वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं।

– जून– 2019 में रेपो दर 5.75 फीसदी हैं।

– रिजर्व बैंक इस दर का उपयोग बैंकों की तरलता घटानें एवं बढ़ाने के लिए करता हैं।

O- Repo Rate

Repo rate refers to the rate at which commercial banks borrow money from the Reserve Bank of India (RBI) in case of shortage of funds. It is one of the main tools of RBI to keep inflation under control. Technically, Repo stands for 'Repurchasing Option'. Present repo rate is 5.75 %.

KAUTILYA ACADEMY
INDORE

www.kautilyaacademy.com

www.facebook.com/KTSZone

PART- A 6 Marks

A- आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए?

आधार	आर्थिक संवृद्धि	आर्थिक विकास
अर्थ	अर्थिक संवृद्धि से अभिप्राय देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है।	आर्थिक विकास में आय बचत एंव निवेश में, परिवर्तनों के साथ–साथ देश के सामाजिक और आर्थिक ढॉचें में प्रगतिशील परिवर्तन से है।
कारक–	इसका संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक, जैसे– उपभोग निवेश में उत्तरोत्तर वृद्धि से है।	इसका संबंध मानव पूंजी में वृद्धि, असमानताओं में कमी और संरचनात्मक परिवर्तनों से हैं।
माप	इसका मात्रात्मक कारकों, जैसे– सकल घरेलू उत्पाद, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा मापी जाती है।	इसकों मापने के लिए गुणात्मक माप जैसे– मानव विकास सूचकांक वैश्विक भूख सूचकांक आदि के द्वारा।
प्रभाव	यह अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाती है।	यह अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ–साथ गुणात्मक परिवर्तन भी लाती है।
अवधारणा	यह एक संकीर्ण अवधारणा है।	यह एक व्यापक अवधारणा है।
प्रासांगिकता	यह सकल घरेलू उत्पादन अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर प्रकाश डालती है।	यह किसी अर्थव्यवस्था में जीवन की गुणवत्ता की उन्नति को प्रदर्शित करता है।
समायावधि	यह एक अल्पकालीन प्रक्रिया है एवं निश्चित समयावधि के लिए होने वाला परिवर्तन है।	यह एक दीर्घकालीन एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
स्वरूप	यह एक स्वचलित प्रक्रिया है।	यह एक निर्देशित प्रक्रिया हैं।

A- Explain the difference in economic growth and economic development.

Economic Growth is defined as the rise in the money value of goods and services produced by all sectors of the economy per head during a particular period. It is a quantitative measure that shows the increase in the number of commercial transactions in an economy.

Economic Development is the process focusing on both qualitative and quantitative growth of the economy.Quality of living standard is the major indicator of economic development.

The key differences between Economic Growth and Development are as follows:

- Economic growth is a narrow concept (It studies only increase in real per capita income) while economic development is a broad concept (it studies increase in real per capita income as well as economic welfare).
- Economic growth is only a quantitative concept whereas economic development is both a quantitative as well as a qualitative concept.
- Economic growth ignores distribution of income. Economic development studies distribution of income.
- Economic growth is an essential element of progress of developed countries. Economic development is an essential element of the progress of under developed countries.

Therefore, an increase in economic development is more necessary for an economy to achieve the status of a Developed Nation.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

B - भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है ? इसको दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।

कारणः :–

– भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक संवृद्धि दर का निम्न होना
– जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
– दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली
– कृषि एक मौसमी व्यवसाय तथा इस पर आधारित उद्योगों का अभाव
– नागरिकों में उद्यमशीलता एवं कौशल तकनीकी ज्ञान का अभाव
– अपर्याप्त योजनाएं एवं स्वरोजगार की इच्छा का अभाव
– बचत एवं निवेश का निम्न स्तर

सुझाव–

– रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, कृषि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना।
– कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चलाएं जाने चाहिए।,
– स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को सहायता प्रदान करना।
– सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
– योजनाओं में रोजगार के कार्यक्रमों को महत्व देना।
– शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना।

C - भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा ?

वैश्वी करण से तात्पर्य एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों के साथ जोड़ना, अर्थात् राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोलता है।

भारत पर प्रभाव–

सकारात्मक–

– तात्कालिक गंभीर संकट से अर्थव्यवस्था उबर गई।
– विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि हुई तथा FDI एवं FIT की आगत में वृद्धि।
– संचार बैंकिंग बीमा इत्यादि क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र में विकास
– कृषि निर्यात बढ़ा तथा खाद्य प्रसंसकरण उद्योग कें तेजी हुई।

B- What is the reason for unemployment in India ? Give some suggestions to remove it.

Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of the economy.

Causes of Unemployment

- Large population.
- Low or no educational levels and vocational skills of working population.
- Inadequate state support, legal complexities and low infrastructura.
- Huge workforce associated with informal sector due to lack of required education/ skills, which is not captured in any employment data. For ex: domestic helpers, construction workers etc.
- The syllabus taught in schools and colleges, being not as per the current requirements of the industries. This is the main cause of structural unemployment.
- Regressive social norms that deter women from taking/continuing employment.

Suggestions to reduce Unemployment -

- Decentralisation of Industrial activities is necessary so that people of every region get employment
- Development of Non-agricultural Subsidiary Industries.
- Entrepreneurs generate employment to many in a country; therefore, the government needs to encourage entrepreneurship among the youth.
- Concrete measures aimed at removing the social barriers for women's entry and their continuous participation in the job market is needed.

C- What has been the impact of globalization on India ?

Globalization has been defined as the process of rapid integration of countries and happenings through greater foreign trade and foreign investment. It is the process of international integration arising from the interchange of world views, products, ideas and other aspects of culture.

IMPACTS OF GLOBALISATION IN INDIA.

Globalisation is a fast ball which swing in both directions.

Positive impact -

1. Globalization has opened new markets for Indian companies to sell their services and products.
2. Foreign investors invested in India to establish their businesses due to cheap resources.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग बढ़ा।

नकारात्मक–

– भारतीय कृषि क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हुई।
– आर्थिक असमानता तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई।
– लघु–कुटीर उद्योगों का पतन हो गया।
– आर्थिक नीतियों पर विश्व बैंक तथा IMF जैसी संस्थाओं का दबाव बढ़ा।
– बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारतीय कंपनियों में गिरावट आयी।

3. Living standard of people in India has been developed due to increase in the wages of skilled and unskilled labor.
4. Companies are producing quality products at competitive prices due to globalization.
5. Globalization strengthened the economic growth of the country due to increase in exports of the country.
6. Infrastructure has been improved; new employment opportunities have been created due to globalization.

Negative effects of Globalization

1. Globalization can damage environment of India due to the establishment of industry at large scale. It has brought water and air pollution e.g. Delhi is one of the most polluted cities of the world.
2. Profits earned from the business will move to the foreign countries although investment of foreigners will bring economic prosperity for short term. The long term advantages will be attained by the foreigners.
3. Human resources can be exploited in India by multinational firms.
4. The entrance of overseas giants can cause closure of the local firms because they can invest more resources as compared to the local or small businesses.

D - प्रवजन के कारणों को समझाइए ?

''प्रवजन निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में विचरण का एक प्रकार है।''

इसके निम्नलिखित कारण है–

1. प्राकृतिक कारण–

– महत्वपूर्ण कारण है, खराब जलवायु तथा दुर्गन भौगोलिक दशाओं वाले क्षेत्र से स्थानान्तरण करना।

2. आर्थिक कारक–

– कृषि योग्य भूमि का न होना।
– औद्योगिक व खनिज संसाधनों का अभाव
– रोजगार तथा भौतिक सुविधाओं का अभाव होना।

3. सामाजिक कारण–

– रीति–रिवाज व परम्पराएँ भी उत्तरदायी होती है।

4. धार्मिक कारण–

– भारत में अलग–अलग धर्म के लोग निवास करते है, जिससे धर्म परिवर्तन एवं प्रसार के कारण लोग स्थान में परिवर्तन कर देते हैं।

D- Explain the causes of migration.

Migration is movement by humans from one area to another, sometimes over long distances or in large groups.

the UN defines migration is a form of geographical mobility between one geography unit to another.

Causes of migration - the causes of migration can be divided into Pull factors and Push factors. Push factors are those which make a person leave a place and Pull factor attracts a person towards a place.

Pull factors-
-Job opportunities
-Better living conditions
-Political and religious freedom
-Education and entertainment
-Better medical care
-Level of industrialisation

Push factors -
-Not enough of jobs.
-Fewer opportunities
-Primitive conditions (infrastructure and social)
-Lack of medical facilities.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

5. सांस्कृतिक कारण–

– जिन स्थानों पर जनसंख्या अधिक होती है वहां से लोग कम जनसंख्या की ओर रहना पसंद करते हैं।

– जन्मदर एंव मृत्युदर के प्रभाव से भी प्रवजन होता है।

6. जनांकिकी कारण–

– जिन स्थानों पर जनसंख्या अधिक होती है वहां से लोग कम जनसंख्या की ओर रहना पसंद करते है।

– जन्म दर एवं मृत्युदर के प्रभाव से भी प्रवजन होता है।

E - क्षेत्रीय असंतुलन क्या है ? इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए।

क्षेत्रीय असंतुलन से अभिप्राय किसी देश के विकास में विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। अर्थात् विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया कि विभिन्न देशों के विकास के साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों की विकास की गति को मन्द रखा जाए।

क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव

1. आर्थिक विकासः–

– क्षेत्रीय एंव खण्डीय असंतुलन देश के आर्थिक विकास में लाभदायी होता है।

– सीमित साधनों का प्रयोग चुने क्षेत्रों में करना पड़ता है।

2. पूँजी निर्माणः–

– समाज में धन का जितना अधिक असमान वितरण होगा, बचतें एंव पूंजी निर्माण उतना ही अधिक होगा।

3. नए उत्पादनों को प्रोत्साहनः–

– नई वस्तुओं की लागत अधिक होती है। असंतुलन के कारण विकसित क्षेत्रों में अधिक धन होने से, वस्तुओं को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जा सकता है।

हानिकारक प्रभाव–

1. साधनों का अनुचित उपयोग–

– क्षेत्रीय एंव खण्डीय असंतुलन के कारण, उन्ही क्षेत्रों के साधनों का उपयोग हो पाता है।

2. क्षेत्रीय संघर्ष–

– असंतुलित विकास क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देता है।

3. प्रवसन को बढ़ावा–

– क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अल्पविकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओ पलायन होने लगता है।

4. नैतिक पतन–

– असंतुलन के कारण उन्नत क्षेत्रों के निवासियों में विलासिता एवं उपभोग की भावना का विकास होता है।

E- What is regional imbalance? Discuss its impact.

Regional Imbalance is situation in which economically developed and backward states or regions coexist in the same country. In this situation some of the states have higher endowments of resources and some have very low resource endowment.

Maharashtra, Tamil Nadu , Gujarat are examples of highly developed states and Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh are underdeveloped . This is creating economic imbalance in our country , this situation is termed as Regional Imbalances.

Impact of Regional Imbalance -

1. Migration: Migration from economically backward area towards economic strongholds For example the rural-urban migration.
2. Social unrest- Differences in prosperity and development leads to friction between different sections of the society causing social unrest. For example Naxalism. Naxalites in India function in areas which have been neglected for long for development purposes/economic prosperity.
3. Aggregation of the imbalance: Once an area is prosperous and has adequate infrastructure for development, more investments pour-in neglecting the less developed regions. So an area which is already prosperous, develops further. For examples- the rate of growth of the four metropolitan cities, as compared to other Metro cities is still higher.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

F- भारतीय राष्ट्रीय आय को मापने में उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए।

1 अमौद्रिकृत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यः–

भारत में आज भी बहुत–सी वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय अमौद्रिक रूप से किया जाता है।

जैसे– बच्चे को पढ़ाना, घर पर एवं उपभोग के लिए खर्च करना।

2. राष्ट्रीय आय मापन की अनेक विधियाँः–

– जैसेः– उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, आदि है। इससे आय संबंधी आकलन में भिन्नता आ जाती है।

3. राष्ट्रीय आय संबंधी आँकड़ों का अभावः–

– अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित आँकड़ों को शामिल नहीं किया जाता है।

4. दोहरी गणना एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य संबंधित समस्या–

– किसी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं दोहरी गणना से संबंधित समस्याऐं उत्पन्न होती है। क्योंकि राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है।

5. स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या–

वित्तीय वर्ष के अंत में बिक्री नहीं हुई तो वस्तुओं के स्टॉक का मूल्यांकन करना बेहद कठिन होता है। क्योंकि वित्तीय वर्ष में किए गए अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है।

6. मूल्य ह्रास के मूल्यांकन की समस्या–

– सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन मूल्य ह्रास की पद्धति एवं दर अनिश्चित होती है।

G- मध्यप्रदेश में औद्योगिक रूग्णता के कारणों को स्पष्ट कीजिए ?

कारण–

– कृषि आधारित राज्य होने पर भी कृषि आधारित उद्योगों की कमी

– पर्याप्त पूँजी का अभाव एवं ससाधनों की कमी।

– बाह्य कारण–

– ऊर्जा सुविधाओं की अनुपलब्धता

F- Describe the problems generated in measuring Indian national income.

The following points will highlight the major Problems in Measuring or calculating National Income.

1. Exclusion of Real Transactions:
In measuring national income from the output side only those items which are purchased and sold through the market are included.
However, all direct sales of various goods and services are excluded.
2. Lack of Reliable Data:
It is observed that many producers —particularly petty producers and traders— do not maintain any accounts of their incomes and even goods produced.
3. Existence of Non-Monetised Sector:
The soundness of national income estimates is affected badly if there exists a large non- monetised sector. This creates valuation problem. In an LDC, there exists an unorganised barter economy where money is not used for transaction purposes.
4. Illegal Income:
illegal incomes are not reported in national income accounts. In other words, illegal forms of economic activity and illegal activities that are not reported to the authority for the purpose of paying taxes are left out from national income accounts.
5. Social services-
It ignores voluntary and charitable work as it is unpaid.
6. Environmental cost : National income estimation doesn't account for environmental costs incurred in the production of goods.

G- Explain the causes of industrial sickness in Madhya Pradesh.

Madhya Pradesh (MP) has predominantly been an agrarian state economy which shows co-existence of poverty and prosperity in the state.
Main causes of low industrialization are -

1. Inadequate capital accumulation
Poor rate of capital formation is considered as one of the major constraints which has been responsible for slow rate of industrial growth in Madhya pradesh.
2. Lack of Infrastructural Facilities-

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– कच्चे माल की कमी
– सरकारी नीतियों का सही क्रियान्वयन न होना।

– आंतरिक कारण–
  – उद्यमकर्ता की अयोग्यता
  – कुशल प्रबंधन का अभाव
  – दोष पूर्ण संयंत्र और मशीने
– अन्य कारण
  – आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता
  – माँग का अभाव
  – विपणन की समस्या
  – आर्थिक कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा में कमी।
  – अनुसंधान एंव नवाचार का निम्न स्तर
  – उचित लेखा परीक्षण का अभाव

H - नवीन औद्योगिक नीति की विशेषताओं को समझाइए।

– 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। इस नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई।

इसकी विशेषताऐं निम्नलिखित हैं–

1. औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति– कुछ उद्योगों को छोड़कर लाइसेसिंग को समाप्त कर दिया गया हैं, परिशिष्ट– II में शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन वाले उद्योगों का लाइसेसिंग, अनिवार्य है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में कमी–
– नई नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्योग रखे गये हैं।
– निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई है।
– वर्तमान में मात्र 3 उद्योगों को आरक्षित रखा गया है।
– सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी अंश को म्येचुअल फंडो, वित्तीय संस्थाओं को बेच दिया जायेगा।
3. MRTP परिसम्पत्ति सीमा समाप्त–
नई औद्योगिक नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की परिसम्पत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
4. उद्योग स्थान का निर्धारण हेतु, सरकार का हस्तक्षेप कम होना।
5. विदेशी निवेश हेतु परिवर्तन किये गए। जिसमें विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन।
6. नवाचार एंव नवप्रवर्तन का संमावेश किया गया हैं।

Madhya pradesh is still backward in respect of its infrastructural facilities and it is an important impediment towards the industrialization of the country.

3. Low exploitation of natural resources including coal,metallic and nonmetallic resources etc. Primary due to the fact that MP has the largest forest cover in India and environment clearance are seldom granted in time.
4. Post reorganization of state (2000)-
MP has turned from power surplus state to power deficit state with a great share of mineral, wealth and power plant gone to chhattisgarh. No industry can grow/operate without power.
5. Regional disparities across regions of MP in terms of industrial growth.
6. Comfort climate is one another non-economic causes for low industrialisation of MP.

H- Explain the features of the New industrial policy.

The New Industrial Policy of 1991 comes at the center of economic reforms that launched during the early 1990s.

The policy has brought changes in the following aspects of industrial regulation:

1. Industrial delicensing- The industrial policy of 1991 has almost abandoned the industrial licensing system. It has reduced industrial licensing to fifteen sectors. Now only 13 sector need license for starting an industrial operation.
2. Public sector de-reservation and privatization of public sector through disinvestment.
3. Amendments to Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969.
The New Industrial Policy of 1991 has abolished the Monopoly and Restrictive Trade Practice Act. In 2010, the Competition Commission has emerged as the watchdog in monitoring competitive practices in the economy.
4. Liberalised Foreign Investment Policy.
Another major feature of the economic reform measure was it has given welcome to foreign investment and foreign technology. This measure has enhanced the industrial competition and improved business environment in the country
5. Foreign Technology Agreements (FTA).
6. Dilution of protection to SSI and emphasis on competitiveness enhancement.

The all-around changes introduced in the industrial policy framework have given a new direction to the future industrialization of the country. There are

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

7. इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की गई। साथ ही निजी क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गये।

I - नीति आयोग क्या है ? इसक उद्देश्य बताते हुए योजना आयोग से भिन्नता दर्शाइए।

नीति आयोग का गठन, 1 जनवरी 2015 को किया गया है। 'नेशनल इंस्ट्रीटयूट फॉर ट्रान्सफॉरमिंग इंडिया' का ही संक्षिप्त रूप नीति है।

यह सरकार को नीतिगत एवं निर्देशात्मक गति प्रदान करने के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा।

नीति आयोग के उद्देश्य–

- केन्द्र व राज्यों द्वारा मिलकर राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को तय करने वाला 'राष्ट्रीय एजेंडा फ्रेम वर्क' तैयार करना।
- सहकारी संधवाद के अंतर्गत राज्यों की भागेदारी बढ़ाना।
- सरकार को दिशा तथा नीति संबंधी थिंक टैंक' के रूप में प्रत्येक स्तर पर सलाहकारी संस्था।
- गांव स्तर से उच्च सरकारी स्तरों की ओर योजना निर्माण करना।
- वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना।
- रणनीतिक और दीर्घवधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढाँचा तैयार करना।
- अंतर–क्षेत्रीय एंव अंतर–विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना।

योजना आयोग की कमियों व नीति आयोग से तुलना–

- नीति आयोग में राज्यों को केन्द्र के बराबर ही मान्यता दी गई और 'सहकारी संघवाद' को आधार बनाया गया है।
- योजना आयोग में बनी योजनाएँ केन्द्र से राज्यों की ओर एक तरफा प्रवाह वाली होती थी।
- योजना आयोग के निरंतर बढ़ते प्रभाव के कारण उसे। 'सुपर–कैबिनेट' की संज्ञा दी जाने लगी थी। जबकि नीति आयोग को सलाहकारी भूमिका में ही रखा गया है।

J - संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अ. ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

ब. ब्लू बॉक्स सब्सिडी

A. ग्रीन बॉक्स सब्सिडी न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया है। इसमें

encouraging trends on diverse fronts. Industrial growth was 1.7 percent in 1991-92 that has increased to 9.2 percent in 2007-08

I- What is the NITI AAYOG? Describing its purpose, show difference from the Planning Commission.

The NITI Aayog is a policy think tank of the Government of India, established with the aim to achieve Sustainable Development Goals and to enhance cooperative federalism by fostering the involvement of State Governments of India in the economic policy-making process using a bottom-up approach.

Purpose of Niti Aayog -

1. Provide a critical directional and strategic input to the development process of India.
2. Serve as a think tank of the Government both at the Center and State-level. Also, provide relevant strategic and technical advice on key policy matters.
3. Try to replace the center-to-state, one-way flow of policy with an amicably settled policy which a genuine and continued partnership of states frames.
4. Monitor and evaluate the implementation of programs and also focus on upgrading technology and building capacity.

Difference btw NITI AAYOG and Planning Commission-

1. The top down approach is reversed in Niti Ayog. It will develop mechanisms to formulate credible plans to the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.
2. While the planning commission formed Central Plans, Niti Ayog will not formulate them anymore. It has been vested with the responsibility of evaluating the implementation of programmes.
3. Planning Commission was an advisory body, and so is Niti Ayog. But the key difference between them is that while the former had powers to allocate funds to ministries and states; this function will be now of finance ministry. Niti Ayog is essentially a think tank and a truly advisory body.

J- Write briefly.

A. Green box subsidy

Green Box subsidies include the amounts spent on Government services such as research, disease control, and infrastructure and food security. This also includes the subsidies given to the farmers that directly don't affect production such as for restructuring the agriculture. Since they are permitted

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

मूलतः वे सभी सरकारी व्यय तथा किसानों के लिये सभी सरकारी व्यय तथा किसानों के लियें सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम शामिल किया जाते है, जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हो। इसमें सभी सरकारी छूटें शामिल है, जैसे– पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, शोध एवं अनुसंधान, कृषि पुनर्सरचना, कीट एवं रोग नियंत्रण आदि।

B. ब्लू बॉक्स सब्सिडी (Blue Bon Subsidy)

ये सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृति या विसंगति में कमी लाने की शर्तों पर प्रदानन की जाती है। इस प्रकार की जाती है। इस प्रकार की छूटें किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिये तथा प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाती है।

जिनका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना है।

K- गरीबी को स्पष्ट करते हुए सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु किये गये सरकारी प्रयासों की व्याख्या कीजिए ?

– गरीबी से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। न्यूतनम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएँ शामिल होती है।

सरकारी प्रयास :–

– मनरेगा :– यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो, 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।
– प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :– मई 2016 में केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालें परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किये गयें।
– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना :– 25 सितम्बर 2014 से भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के, 15–35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास के लिए शुभारंभ की गई।
– प्रधानमंत्री आवास योजना :– इसके तहत कमजोर आय वर्ग व गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना।

अन्य :–

– एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं
– न्यूनतम आवश्यकता योजना

in WTO regime, the most developed countries have kept providing subsidies to their farmers.

B. Blue box subsidy

Blue Box refers to a category of domestic support or subsidies under the WTO's Agreement on Agriculture.

Blue box supports are subsidies that are tied to programmes that limit production. Hence it is an exception to the general rule related to agricultural support. The Blue box subsidies aim to limit production by imposing production quotas or requiring farmers to set aside part of their land. It covers payments directly linked to acreage or animal numbers.

According to the WTO, the Blue Box is the "amber box with conditions" — conditions, designed to reduce distortion.

K- Explaining the poverty, explain the government's efforts made by the government for poverty alleviation.

Poverty is an economic state where people are experiencing scarcity or the lack of certain commodities that are required for the lives of human beings like money and material things. Therefore, poverty is a multifaceted concept inclusive of social, economic and political elements.

On the basis of social, economical and political aspects, there are different ways to identify the type of Poverty:

1. Absolute poverty.
2. Relative Poverty.
3. Situational Poverty.
4. Generational Poverty.
5. Rural Poverty.
6. Urban Poverty.

Removal of poverty has been the biggest challenge in India. The Indian government is dealing with the same with two methods by

promoting economic growth and by anti poverty programmes-

1. Integrated Rural Development Programme:

The main aim is to provide support to the rural poor in the form of subsidy and bank credit for productive work opportunities through successive plan periods.

2. Jawahar Rozgar Yojana /Jawahar Gram Samriddhi Yojana JGSY):

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– प्रधानमंत्री रोजगार योजना

The purpose was to generate good work prospects for the unemployed in rural areas by creating economic infrastructure, community and social asset.

3. Employment Assurance Scheme:
This scheme was launched in the year 1993. It mainly covers drought-prone, desert, tribal and hill area blocks.It was expected to lead to the creation of robust economic and social infrastructure and address the needs of people.
4. National Old Age Pension Scheme.
5. Rural Housing Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana (PMGAY):
PMGAY is a government flagship programme, created for providing housing for the Indian rural poor.

L- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर लघु निबंध लिखिए ?

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अगस्त 2017 में की गयी। यह योजना पूरी तरह कृषि केन्द्रित योजना है।

उद्देश्य :– इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को रोकना है।

विशेष :–

– इस योजना से, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा।
– खेत से खुदरा ब्रिकी केंन्द्रो तक प्रबन्धन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा।
– किसानों को बेहतर मूल्य तथा आय को दुगुना करने का प्रयास।

योजना से लाभ :–

– किसानों की आय दुगुना करने के दिशा में सरकारी प्रयास
– देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढावा मिलेगा
– इस योजना से रोजगार के अवसर बढे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है।

L- Write a Short Essay on the Prime Minister's Kisan Sampdha Yojana.

Government of India (GOI) has approved a new Central Sector Scheme – Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) with an allocation of Rs. 6,000 crore for the period 2016-20 coterminous with the 14th Finance Commission cycle.

PM Kisan SAMPADA Yojana is a comprehensive package which will result in the creation of modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet.

The objective of PMKSY is to supplement agriculture, modernize processing and decrease Agri-Waste.

The following schemes will be implemented under PM Kisan SAMPADA Yojana :

1.Mega Food Parks
2.Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure
3.Creation/ Expansion of Food Processing/
4.Preservation Capacities (Unit Scheme)
Infrastructure for Agro-processing Clusters
5.Creation of Backward and Forward Linkages
6.Food Safety and Quality Assurance Infrastructure
7.Human Resources and Institutions

Impact of PMKSY

1. The implementation of PMKSY will result in creation of modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet.
2. It will provide a big boost to the growth of food processing sector in the country.
3 It will help in providing better prices to farmers and is a big step towards doubling of farmers' income.
4. It will create huge employment opportunities especially in the rural areas.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

PART- A 15 Marks

A- आर्थिक नियोजन क्या है ? इसके उद्देश्य को बताते हुए इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए।

देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक, कार्यों में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एंव सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण करना।

नियोजन का उद्देश्य :–

– निरंतर दीर्घावधि सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि।
– मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, जिससे पूर्ण रोजगार प्राप्त हो।
– धन तथा आय का समान वितरण।
– संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।
– निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना।
– सामाजिक न्याया व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
– तीव्र आर्थिक विकास के साथ–साथ समावेशी विकास पर बल।
– संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना।
– कृषि एवं उद्योगो का समन्वित विकास करना।
– निवेश एवं पूँजी निर्माण को बढावा देना।

1. राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर –

– आदेशात्मक नियोजन :– यह एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था है जिससे राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्पक्ष होता है।
– निर्देशात्मक नियोजन :– यह एक विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था है जिससे राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का, सांकेतिक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है।

2. लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर –

– संरचनात्मक नियोजन :– आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्तमान स्वामित्व के ढाँचे एवं संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन संरचानात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे :– भूमि सुधार, बैंको का राष्ट्रीयकरण आदि।
– प्रकार्यात्मक नियोजन :– इसमें स्वामित्व में ढाँचे में परिवर्तन के बिना अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाती है।

3. क्षेत्रीयता के आधार पर –

– राष्ट्रीय नियोजन :– केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना। जैसेः– स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन करना।
– क्षेत्रीय नियोजन :– जब किसी क्षेत्र–विशेष को ध्यान में रखकर योजनाओं तथा रणनीतियों का निर्माण करना। जैसे :– [illegible] विकास परियोजनाएँ।

A- What is financial planning? Explain its types while explaining its purpose.

Financial planning means deciding in advance how much to spend, on what to spend according to the funds at your disposal.

Financial Planning is the process of estimating the capital required and determining its competition. It is the process of framing financial policies in relation to procurement, investment and administration of funds of an enterprise.

There are three types of financial plans, viz.,

1. Short-term financial plan is prepared for maximum one year. This plan looks after the working capital needs of the company.
2. Medium-term financial plan is prepared for a period of one to five years. This plan looks after replacement and maintenance of assets, research and development, etc.
3. Long-term financial plan is prepared for a period of more than five years. It looks after the long-term financial objectives of the company, its capital structure, expansion activities, etc.

Purpose of Financial Planning -

1. It Facilitates Collection of Optimum Funds: The financial planning estimates the precise requirement of funds which means to avoid wastage and over-capitalization situation.
2. Financial Planning helps in ensuring a reasonable balance between outflow and inflow of funds so that stability is maintained.
3. Financial Planning helps in making growth and expansion programmes which helps in the long-run of government policies and plans.
4. Financial Planning reduces uncertainties with regards to changing market trends which can be faced easily through enough funds.
5. Financial planning acts as a basis for checking the financial activities by comparing the actual revenue with estimated revenue and actual cost with estimated cost.

Limitations of Financial Planning Financial Planning has many limitations, they are as below :

1. Financial resources are not unlimited. Very heavy taxation may adversely affect the propensity to save.
2. There is a vast non-monetized sector in underdeveloped economies as the people live on subsistence level and much of the produce is not brought to the market in such economies. The monetized sector is small. On account of the imbalance between these two sectors, shortages in

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

4. प्रक्रिया के आधार पर –

– केंन्द्रीकृत नियोजन :– इसमें नियोजन की समस्त सत्ता केन्द्र में निहित होती है जिसका स्वरूप ऊपर से नीचे की ओर होता है।

– विकेंन्द्रीकृत नियोजन :– इसमें योजनाओं का निर्माण, केन्द्र राज्य, एवं स्थानीय सरकार सभी की सहभागिता से होता है। इसका स्वरूप नीचे से ऊपर की ओर होता है।

5. अवधि के आधार पर –

– दीर्घकालिक नियोजन :– इसके अन्तर्गत योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि होती है। जैसे :– सफल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि।

– अप्लकालिक नियोजन :– इसके अंतर्गत वार्षिक योजनाओं का निमार्ण कर मूल्यांकन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे :– अनवरत योजना।

B - आर्थिक विकास के तत्वों का उल्लेख करते हुए आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए।

आर्थिक विकास से आशय अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिर्वतनों से है। यह परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हो सकते है।

आर्थिक विकास = आर्थिक वृद्धि + गुणात्मक परिवर्तन

आर्थिक विकास के तत्वों का आर्थिक एवं गैर – आर्थिक तत्वों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है।

प्रभावित करने वाले कारक :–

1. पूंजी निर्माण :– किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि के लिये पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक है।

– जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर उच्च रही है उन्होने तीव्र आर्थिक संवृद्धि प्राप्त की है।

– भारत में 1970 के दशक में पूंजी निर्माण की दर GDP का मात्र 15% थी जबकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्माण की दर 30% से अधिक है।

2. औद्योगीकरण की तीव्र वृद्धि दर :– तीव्र आर्थिक संवृद्धि के लिये औद्योगीकरण की दर भी उच्च होनी चाहिये।

3. सेवा क्षेत्र की बढती भूमिका :– वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत के GOP में लगभग 50% का योगदान दे रहा है। साथ ही नये–नये रोजगार का सृजन भी होता है।

4. राजनीतिक कारक :– एक स्थिर, शक्तिशाली, तथा कुशल सरकार, पारदर्शी नीतियाँ होने, और उनको कुशलतापूर्वक लागू करने से निवेशकों को आकर्षित करती है।

supply are likely to result in an inflationary rise in prices thus upsetting physical targets.

3. If the shortages in supplies are made up through imports, the problem of balance of payments will become serious.

4. As Prof. Dobb says " The problem of industrialization in backward countries is essentially not financial but a problem of economic organization" and availability of physical resources.

B- Describe the factors influencing Economic Prosperity and Economic Development while mentioning the elements of economic development.

Economic development is the growth of the standard of living of a nation's people from a low-income (poor) economy to a high-income (rich) economy. When the local quality of life is improved, there is more economic development.

Economists generally agree that economic development and growth are influenced by four factors: human resources, physical capital, natural resources and technology. Highly developed countries have governments that focus on these areas.

Factors that Influence the Economic Development of a Country -

(A) Economic Factors in Economic Development:

(1) Capital Formation:

The strategic role of capital in raising the level of production has traditionally been acknowledged in economics.

(2) Natural Resources:

The principal factors affecting the development of an economy is the natural resources.

(3) Marketable Surplus of Agriculture:

Increase in agricultural production accompanied by a rise in productivity is important from the point of view of the development of a country.

(4) Conditions in Foreign Trade:

(B) Non-Economic Factors in Economic Development:

(1) Human Resources:

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

5. विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियाँ :– वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुडाव हो गया।
   विदेशी व्यापार नीति, विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार भी आर्थिक संवृद्धि की दर को प्रभावित करत है।
6. मानव संसाधन :–
7. उद्यमशीलता :–
8. तकनीकी उन्नति :–
9. आर्थिक प्रणाली :–
10. प्राकृतिक संसाधन :–

C - भारत में आज की स्थिति में मनरेगा की प्रासंगिकता पर विस्तृत निबंध लिखिए।

– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरूआत, 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश से की गई, संसद द्वारा यह अधिनियम के रूप में सितम्बर 2005 में पारित किया गया था।
   2 अक्टूम्बर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण, रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। यह कानून एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।
   मनरेगा में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों के कम से कम 33% महिलाएँ होनी चाहिये। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है।
– रोजगार के लिये आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह, रोजगार श्रमिक के निवास से 5 किमी. के अन्दर होगा। इससे अधिक दूरी होने पर परिवहन भत्ता दिया जाऐगा।
   यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार नही प्रदान किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा।
– 'संपूर्ण ग्रामीण योजना' तथा 'काम के बदले अनाज योजना' का इसमें विलय कर दिया गया है।
   मनरेगा के अंतर्गत अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्रों जैस– जलसंभरण, ग्रामीण संडक इत्यादि।
   मनरेगा के लाभ :–

Human resources are an important factor in economic development. Man provides labour power for production and if in a country labour is efficient and skilled, its capacity to contribute to growth will decidedly be high.

(2) Technical Know-How and General Education:
As the scientific and technological knowledge advances, man discovers more and more sophisticated techniques of production which steadily raise the productivity levels.

(3) Social Organisation:
Mass participation in development programs is a precondition for accelerating the growth process. However, people show interest in the development activity only when they feel that the fruits of growth will be fairly distributed.

(4) Desire to Develop:
Development activity is not a mechanical process. The pace of economic growth in any country depends to a great extent on people's desire to develop.

C- Write a detailed essay on the relevance of MNREGA in today's situation in India.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), also known as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is Indian legislation enacted on August 25, 2005. The MGNREGA provides a legal guarantee for one hundred days of employment in every financial year to adult members of any rural household willing to do public work-related unskilled manual work at the statutory minimum wage.

Objective of the Act

The objective of the Act is to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

Key Features:

1. Demand driven scheme: Worker to be hired when he demands and not when the Government wants it.
2. Gram Panchayat is mandated to provide employment with 15 days of work application, failing which worker is entitled to unemployment allowance
3. Payment of wages within 15 days of competition of work, failing which worker is entitled to delay compensation of 0.05%/ day of wages earned

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

- रोजगार में वृद्धि
- महिलओं तथा पिछडे वर्गों का वित्तीय समावेशन
- न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

वर्तमान स्थिति :– वर्तमान में लगभग 4.7 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। इसमें महिलाओं की 54% अनुसूचित जाति की 22% और अनुसूचित जनजाति की 17% भागीदारी रही। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इससे, महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही है।

4 Minimum one-third of the workers should be women
5. Wages to be paid according to the Minimum Wages Act 1948 for agricultural labourers in the State
6. Social Audit to be done by Gram Sabha

Recent developments:

1 Direct Benefit Transfer: Wages are electronically transferred to the worker's bank/ post office accounts through National Electronic Fund Management System (NeFMS)
2. GeoMGNREGA: Geo-tagging all assets created under MGNREGA

Achievements:

1. MGNREGA has been a powerful instrument for empowerment of poor women through its effect on livelihood security and social protection.
2. Reduced distressed rural to urban migration and also seasonal migration by providing work closer to home and decent working conditions.
3. Has helped in the upliftment of SCs and STs through creation of livelihood opportunities.
4. Sustainable assets have been created linked to conservation of natural resources and has helped in overall development of Gram Panchayats.
5. The average daily wage rate of farm workers has grown sharply after MGNREGA.

Issues:

1. Insufficient budget allocation:
2. Shift to Supply-driven programme:
   According to Ne-FMS guidelines, states won't be allowed to generate employment above the limits agreed by Approved labour Budget. This has made the programme supply-driven.
3. Poor wages rate:
   MGNREGA wages are lower than minimum wages in most states.This could push marginalized section to take up vulnerable and hazardous jobs.

4. Corruption at various levels in implications of the scheme.

D - रिजर्व बैंक एक शीर्ष संस्था है ? इसके कार्यो का उल्लेख कीजिए ?

भारत का केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934 के तहत् 1 अप्रैल, 1935 को 5 करोड़ रूपयें की अधिकृत पूँजी से हुई थी। यह 5 करोड़ रूपये की पूँजी 100 रूपए मूल्य के 5 लाख अंशों (Shares) में विभाजित थी। प्रारंभ में लगभग समस्त अंश पूँजी का सवामित्व गैर–सरकारी अंशधारियों के पास था, किन्तु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के

D- Reserve Bank is a top institution, mention its functions.

The Reserve Bank of India is the Central Bank of India, which means it is at the apex of the banking structure of the economy. It is one of the main governing body and regulatory body in India and helps the government in its role as a business facilitator.

The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

रिजर्व बैंक का मुख्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था। तत्पश्चात् 1937 में इसे मुम्बई (वर्तमान मुख्यालय) हस्तान्तरण कर दिया गया। आर.बी. आई. के 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

रिजर्व बैंक के कार्य

1. नोटों का निर्गमनः– रिजर्व बैंक को एक रूपये के सिक्के/नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत मे विभिन्न मूल्यवर्ग (Various Denominations) के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक रूपये के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटें सिक्कों का देशभर में वितरण का कार्य करता है। करेन्सी जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति (Minimum Reserve System) को अपनाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रूपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए।
2. सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना :– रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकर, एजेण्ट एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना है। यह केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग कार्यों को सम्पन्न करता है तथा सरकार को आर्थिक एवं मौद्रिक नीति संबंधी मामलों में भी सलाह देता है। यह सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी करता है।
3. बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करनाः– रिजर्व बैंक देश में अन्य बैंकों के लिए वहीं कार्य करता हैं, जोकि अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। यह व्यापारिक बैंकों का बैंकर ही नही, बल्कि अंतिम ऋणदाता भी है। भारत में RBI केन्द्रीय बैंक की भूमिका का निर्वहन करता है।
4. साख–नियंत्रण :– रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण करने का कार्य भी सम्पन्न करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिमाणात्मक व गुणात्मक साख नियंत्रण उपायों का उपयोग करता है।
5. विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण :– रूपये के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय–विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है।

The Central Office of the Reserve Bank is in Mumbai. After nationalisation in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the Government of India.

Functions of the RBI

- The issuer of Currency: The RBI is the only authorized body that can issue currency in the country. So they print, distribute and regulate the flow of currency in the economy.
- Banker to the Government: Even the Central and State government need basic banking functions. The RBI provides them with these facilities like depositing monies, remittances etc. It can also make advances and provide loans to the government whenever necessary.
- Banker to other Banks: The Reserve Bank of India also supervises all other commercial banks in the country. It provides financial assistance to these banks like short-term loans and advances. The RBI also will dictate interest rates and the CRR limits to the commercial banks.
- Regulator of Foreign Exchange: It is the function of the RBI to maintain the value of the rupee in the global economy. It does so by acting as the custodian of foreign exchange reserves in the country. It maintains enough reserves to battle against fluctuations.
- Controls Credit in the Economy: This can be said to be the primary function of the Reserve Bank of India, the control of credit and money in the market. It uses qualitative and quantitative methods to either expand or contract the available credit in the economy according to circumstances.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
INDORE

6. विकासात्मक भूमिका :– राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करता है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय मजबूती प्रदान करता है।

7. अन्य कार्य :– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आर्थिक विकास पर अधिक बलदेने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक कार्यों का लगातार विस्तार हुआ है। बैंक द्वारा विकास संबंधी और भी बहुत से कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों में समाशोधन गृह का कार्य, कृषि साख की व्यवस्था करना, आर्थिक ऑकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना, सरकारी प्रतिभूतियों व व्यापारिक बिलों का क्रय–विक्रय करना, ऋण देना, मूल्यवान वस्तुओं का क्रय–विक्रय करना आदि कार्य आते हैं। वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।

8. RBI द्वारा ब्याज की दर, तरलता व बैंकों का नियंत्रण मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जाता हैं जो वर्ष भर में एक बार प्रस्तुत की जाती हैं तथा इसकी समीक्षा प्रत्येक तीन माह पर की जाती हैं।

– सूचना प्रकाशित करना :– रिजर्व बैंक मुद्रा, साख तथा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण आकड़ें वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक व मासिक अवधि में प्रकाशित होते हैं।

– वार्षिक प्रकाशनः– भारत की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर साख्यिकी की हस्तपुस्तिका।

– मासिक प्रकाशन :– भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इनफार्मेशन रिव्यू।

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

PART- B

A - यू पी आई

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI सिस्टम की शुरूआत की।

– RBI गवर्नर रघुराम राजन ने 11 अप्रैल 2016 को मुम्बई में इसे लान्च किया।

– यह प्रणाली डिजिटल तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस स्ट्रक्चर पर कार्य करती हैं।

B - प्रतिभूति बाजार

प्रतिभूति बाजार पूँजी बाजार का एक अंग है अर्थात वह वित्तीय बाजार जहाँ से शेयर, प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, म्युचुअल फंड इत्यादि से दीर्घावधिक पूंजी की व्यवस्था की जाती है प्रतिभूति बाजार कहाँ जाता हैं।

C - चुनावी बॉण्ड

– भारत सरकार ने 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉण्ड योजना अधिसूचित की।

– इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले नकद व गुप्त चंदे के चलन को रोकना है।

– चनावी बॉण्ड केवल 15 दिनों के लिए वैध होगे।

D - अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर–

अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है।

E - भारत माला परियोजना–

यह एक राष्ट्रीय राजगार्म परियोजना है। इसके तहत 51000 किमी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जायेगा तथा देश के सीमावर्ती व तटीय राज्यों में यह निर्माण किया जायेगा।

A- UPI

Unified Payments Interface (UPI) is an instant real-time payment system developed by National Payments Corporation of India facilitating inter-bank transactions. The interface is regulated by the Reserve Bank of India and works by instantly transferring funds between two bank accounts on a mobile platform.

B- Securities market

Securities market is a component of the wider financial market where securities can be bought and sold between subjects of the economy, on the basis of demand and supply. Securities markets encompasses stock markets, bond markets and derivatives markets where prices can be determined and participants both professional and non professionals can meet.In India SEBI is a watchdog over security market.

C- Electoral Bond

Electoral Bond refers a bond which has its specified face value, mentioned on it like a currency note.

These bonds can be used by the individuals, institutions and organizations to donate money to the political parties.

These electoral bonds will be available in the denomination of Rs. 1,000, Rs. 10,000, Rs. 1 lac, Rs. 10 lacs and Rs. 1 crore.

D- Differences in Economics and Economy

The economy is, "the relationship between production, trade and the supply of money in a particular country or region".

Economies can vary in size from a local neighborhood marketplace to a global economy.

On the other hand Economics is an academic discipline and a branch of the social sciences concerned with observation and analysis of the production, consumption, and transfer of wealth.

E- Bharatmala Pariyojna

Bharatmala Pariyojana is a centrally-sponsored and funded road and highways project of the Government of India.

Under the plan the government intends to develop 83,677 km of highways and roads at an investment of around Rs 7 lakh crore over the next five years.

It focuses on the new initiatives like development of Border and International connectivity roads, Coastal & port connectivity roads, improving efficiency of National Corridors, Economic corridors and others.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

F - मध्यप्रदेश वित्त निगम–

– म.प्र. वित्त निगम की स्थापना– 30 जून 1955 को की गई। जिसका मुख्यालय इंदौर में स्थित हैं।

– यह निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

G - वैश्वीकरण

वैश्वीकरण से तात्पर्य एक देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। अर्थात् जब कोई राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोलता हैं।

– आयात एवं निर्यात पर सीमा शुल्क में कमी तथा 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' में सुधार।

H - औद्योगिक रूग्णता–

रूग्ण औद्योगिक कंपनी एक्ट के अनुसार– ''ऐसी कंपनी जिसका किसी भी वित्त वर्ष के अंत में संचित हानि उसके संपूर्ण निवल मूल्य के समतुल्य या अधिक हो।

– किसी वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी ने पूर्व चार वित्तीय वर्ष में अपने औसत निवल मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक हानि उठाई हो साथ ही लगातार तीन तिमाहियों में अपने ऋणदाताओं को ऋण अदायगी में असफल रहे, औद्योगिक रूग्णता कहलाती हैं।

I - ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट

– मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु आयोजित किया जाता है।

– इसका प्रारंभ– 2007 से हुआ था जो अभी तक पाँच समिट आयोजित कर चुका है।

– आगामी समिट अक्टूबर– 2019 में इंदौर में आयोजित होगी।

J - आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है?

किसी देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का आकलन कर निश्चित, समयावधि में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाये गये कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आर्थिक नियोजन कहते हैं।

F- Madhya Pradesh Finance Corporation

Madhya Pradesh Financial Corporation is the premier institution of the state, engaged in providing financial assistance and related services to small to medium sized industries.

Incorporated in the year 1955.

MPFC is a well knit organisation with its headquarters at Indore.

G- Globalization

Globalization is a process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology.

This process has effects on the environment, on culture, on political systems, on economic development and prosperity, and on human physical well-being in societies around the world.

H- Industrial Sickness

Industrial sickness is defined all over the world as "an industrial company (being a company registered for not less than five years) which has, at the end of any financial year accumulated losses equal to, or exceeding its entire net worth and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year".

I- Global Investors Summit

Global Investors Summit is a biennial business summit organized by the Government of Madhya Pradesh in Indore, the commercial capital of central India to attract domestic and foreign investment for development of the state.

Most recent GIS was held in 2016.

It is organised by Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam.

J- What does economic planning mean?

Economic Planning refers to any plans of economic activity which point to achieve specific social and economic outcomes.

The planning mechanism involves the specific economic or social outcomes.

The philosophy of planning is that only markets and price system cannot ensure the welfare of citizens.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

K - सकल घरेलू उत्पाद

एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंन्तर्गत सभी निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग (GDP) कहलाता है।

L - जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलें–

आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सहायता से जीनों को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में आसानी से डाला जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त फसल को पारजीनी फसल कहा जाता हैं।

जैसे – बीटी बैंगन, बीटी कपास इत्यादि।

M - भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण–

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 2008 में स्थापित, जो विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में खाद्य संबंद्ध विषयों को निपटानें वाले अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है।

उद्देश्य– खाद्य वस्तुओं की शुद्धता जाँचने के लिए।

मुख्यालय– नई दिल्ली स्थित है।

N - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सरकार द्वारा नियंत्रित एंव संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है।

– सरकार के आधिपत्य वाले सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या इससे अधिक होती है।
– औद्योगिक नीति– 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय स्थान प्राप्त किया।

O - मूल्य वर्द्धित कर

– यह एक अप्रत्यक्ष कर हैं, जो उत्पादन से लेकर बिक्रीय के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्य संवर्द्धन पर चुकाया जाता है।
– 1 अप्रैल 2013 से वैट लागू करने वाल प्रथम राज्य हरियाणा था।
– भारत में वैट, केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर लागू किया गया।
– यह केन्द्र में सेनवैट और राज्य में, बिक्रीकर के रूप में लगाया गया है।

K- Gross Domestic Product

Gross domestic product (GDP) is a monetary measure of the market value of all final goods and services produced in a specific time period, often annually.

Gross domestic product tracks the health of a country's economy.

L- Genetically Modified Crops

Genetically modified crops (GM crops) are plants used in agriculture, the DNA of which has been modified using genetic engineering methods.

In most cases, the aim is to introduce a new trait to the plant which does not occur naturally in the species.

Example - Golden Rice ,BT Cotton.

M- Food Safety and Standards Authority of India

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is an autonomous body established under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.

The FSSAI has been established under the Food Safety and Standards Act, 2006.

FSSAI is responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety.

N- Public sector undertaking

A state-owned enterprise in India is called a public sector undertaking (PSU) or a public sector enterprise.

These companies are owned by the union government of India or one of the many state or territorial governments or both.

The company stock needs to be majority-owned by the government to be a PSU.

O- Value added tax

A value-added tax (VAT) is a consumption tax placed on a product whenever value is added at each stage of the supply chain, from production to the point of sale.

In some countries VAT is known as GST.

VAT is collected by the end retailer and is usually a flat tax, and is therefore frequently compared to a sales tax.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

PART- B 6 Marks

A- अर्थव्यवस्था क्या है ? इसके क्षेत्रों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है ?

जब किसी देश को उसकी समस्त, आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में परिभाषित करते है, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते है।

जहाँ आर्थिक गतिविधि से तात्पर्य देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा सीमित संसाधनों के प्रयोग तथा वितरण से संबंधित होती है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र :– अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को निम्न लिखित तीन क्षेत्रों में बांटा गया है–

– प्राथमिक क्षेत्र :– इसके अन्तर्गत उन आर्थिक, गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनको प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे – कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, खनन आदि।

– द्वितीयक क्षेत्र :– इस क्षेत्र में वे सभी क्रिया कलापों को शामिल किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों को रूप बदल कर मूल्यवर्द्धन कर देते है। जैसे – निर्माण, विनिर्माण, आदि।

– तृतीयक क्षेत्र :– वह आर्थिक क्रियाकलाप जिनका संबंधा सेवा गतिविधियों से जुडा होता है। इसमें मानव श्रम–शक्ति की भूमिका अहम होती है। जैसे – बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन आदि।

A- What is the economy? What is its role in the Indian economy ?

An economy is an area of the production, distribution, or trade, and consumption of goods and services by different agents. Understood in its broadest sense, 'The economy is defined as a social domain that emphasize the practices, discourses, and material expressions associated with the production, use, and management of resources'.

Economic activity is spurred by production which uses natural resources, labor, and capital.

Areas of Economy: - Economic activities in the economy have been divided into the following three areas-

- Primary sector: - It covers economic, activities which are produced by the direct exploitation of natural resources. Eg - agriculture, animal husbandry, fisheries, mining etc.
- Secondary area: - In this area all those activities are incorporated, which transforms the nature of natural resources and adds value to it. Such as manufacturing, manufacturing, etc.
- Tertiary sector: - The economic activities that are related to service activities. The role of human labor is crucial in this. Such as banking, insurance, education, tourism etc.

B- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का उद्देश्य 'तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास' को लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया।

– आर्थिक विकास :–
- – सफल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि दर प्राप्त करना।
- – कृषि क्षेत्र में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% वृद्धि करना।

– गरीबी और रोजगार :–
- – योजना के अंत तक गरीबी में 10% की कमी लाना।
- – गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य एवं रोजगार का सृजन करना।

– शिक्षा :–
- – लैंगिक तथा सामाजिक कमी को दूर करना।
- – इस योजना के अंत तक, नवजात शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृ मृत्युदर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना।
- – कुल प्रजनन दर को 2.1 करना।

B- Discuss the purpose of the 12th Five Year Plan.

12th Five Year Plan 2012-17 as per the draft document released by the Planning Commission aims at a growth rate of 8%.

Twelfth Five Year Plan focuses on Growth – Growth which is Faster ,Inclusive and Sustainable.

Purpose of 12th Five year Plan -

ECONOMIC GROWTH
- Real GDP growth at 8%.
- Agriculture growth at 4%.
- Manufacturing growth at 10%.
- Every state must attain higher growth rate than the rate achieved during 11th plan.

POVERTY AND EMPLOYMENT
- Poverty rate to be reduced by 10% than the rate at the end of 11th plan.
- 5 Crore new work opportunities and skill certifications in non-farm sector.

EDUCATION
- Mean years of schooling to increase to 7 years.
- 20 lakh seats for each age bracket in higher education.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– **ग्रामीण अवसरंचना :–**
  – अवसंरचना में निवेश को बढाकर GDP के 9% पर लाना।
  – सभी गाँवों को बारहमासी सडकों से जोडना।
  – योजना के अंत तक सभी गाँव को बिजली उपलब्ध ा कराना।
– **पर्यावरण और धारणीयता :–**
  – हरित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेम्टेयर की वृद्धि।
  – नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, 30,000 मेगावाट की वृद्धि।
– **सेवा :–**
  – 90% भारतीय परिवारों तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना।

C - नगरीकरण का अर्थ बताते हुए नगरीय क्षेत्र के मुद्दों को बताइए।

नगरीकरण विकास प्रकृिया का ही एक अंग हे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहारों में जाकर रहना और काम करना भी 'नगरीकरण' है।

नगरीय क्षेत्र के मुद्दे :–

– मलिन बस्तियाँ :– जनसंख्या वृद्धि से, नगदीकरण अनियोजित ढंग से हो जाता है जिससे आवास सुविधा के अभाव में अवैध बस्तियो का विकास होता है।
– शहरी गरीबी :– असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले आदि एक व्यापक समस्या है जिससे चोरी, नशाखोरी, आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है।
– यातायात की समस्या :– बढती आबादी के कारण वर्तमान समय में बडे शहरों में ट्रेफिक समस्या ने एक चुनौती का रूप धारण कर लिया है। जैसे – दिल्ली, इंदौर, कानपुर आदि शहरों में।
– नगरीय प्रदूषण :– प्राकृतिक वनस्पति पेड पौधों आदि कम होते जा रहे है और, शहरो वाहन, उद्योग आदि से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढता जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए एक वैश्विक समस्या, बन चुकी है।
– जल आपूर्ति सेवा :– वर्तमान में शहरों में जल आपूर्ति समस्या अत्यधिक है।
– सफाई–प्रबंधन :– शहरों मे स्वच्छता की कमी के कारण, बीमारियों का रवतरा बढ़ जाता है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन काफी हद तक कारगार सिद्ध हुआ है।
– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :– शहरों मे ठोस अपशिष्ट के लिए कोई व्यवस्था नही होती है। जिससे खतरनाक बीमारियाँ पनपने का मौका मिलता है।

- End gender gap and social gap in school enrollment.

INFRASTRUCTURE

- Investment in Infrastructure at 9% of GDP Gross Irrigated Area 103 million hectare (from 90 million hectare)
- Electricity to all villages; Reduce AT&C losses by 20%.
- Connect Villages with All Weather Roads National and State highways to a minimum of 2 lane standard.

ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

- Increase green cover by 1 million hectare every year.
- 30,000 MW renewable energy during Five Year Period.
- Emission intensity of GDP to be reduced to 20-25% of 2005 levels by 2020.

C- Explaining the meaning of urbanization, discuss the issues of urban area.

Urbanization (or urbanisation) refers to the population shift from rural areas to urban areas, the gradual increase in the proportion of people living in urban areas, and the ways in which each society adapts to this change.

Issues of Urbanisation

1. Degradation of environmental quality: Due to urbanization, there is environmental degradation especially in the quality of water, air and noise.
2. Housing: It is another intense problem due to urbanization in India. Overcrowding leads to a constant problem of scarcity of houses in urban areas.
3. Unemployment: The problem of joblessness is also serious as the problem of housing.
4. Slums and Squatter Settlements: The fast urbanisation in combination with industrialisation has resulted in the enlargement of slums.
5. Water: Supply of water started falling short of demand as the cities grew in size and number.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

D - ग्रामीण साख के लिये संस्थागत स्त्रोतों के योगदान को बताइए।

ग्रामीण साख के संस्थागत गत स्त्रोत सहाकारी समिति, वाणिज्यिक बैंक आदि है जिससे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

1982 में शिवरमन कमेटी की सिफाारिश के बाद नाबार्ड की स्थापना से ग्रामीण साख में क्रांतिकारी परिवर्तन आया।

वाणिज्यिक बैंक :– 1955में भारतीय बैंक ने ग्रामीण साख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः 19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ग्रामीण साख का 42% हिस्सा, व्यापारिक बैंको द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :– 2 अक्टूम्बर 1975 को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की गई। इनका मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना।

नाबार्ड :– कृषि वित्त एवं साख संबंधित आदि के संदर्भ में शीर्ष संस्था है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोडना प्रमुख है।

ग्रामीण साख का निरीक्षण करना एवं संस्थागत साख को बढावा देना।

भूमि विकास बैंक :– यह ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्त प्रदान करती है।

सहकारी साख संस्थाएँ :– वर्तमान में सहकारी संस्थाएँ कुल ग्रामीण साख का लगभग 30% उपलब्ध कराती है।

– उद्देश्य :–
  – कृषकों को साख उपलब्ध कराना।
  – क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना।

D- Explain the contribution of institutional sources for Rural credit.

68.84% of the population in India is rural based and majority of them depend on agriculture for a living.Enhanced and stable growth of the agriculture sector is important as it plays a vital role not only in generating purchasing power among the rural population by creating on-farm and off-farm employment opportunities but also through its contribution to price stability and food security.

The institutional credit has been conceived to play a pivotal role in the agricultural development of India. A large number of institutional agencies are involved in the disbursement of credit to agriculture. However, the persistence of money lenders in the rural credit market is still a major concern.

The following five major institutional sources of rural credit in India. They are:

1. Co-Operative Credit Societies

The co-operative societies are supposed to be the cheap-est and most important source of rural credit.

2. Land Development Banks

Land devel-opment bank (formerly known as land mortgage banks) mainly provide long-term loans to farmers against the mortgage of their lands at low rates of interest over a period of 15 to 20 years.

3. Commercial Banks

One of the objectives of nationalisation of com-mercial banks was to ensure a smooth flow of credit to agriculture and small-scale industries—the two top priority sectors of Indian economy.

4. Regional Rural Banks

In 1975, the Gov-ernment set up a network of regional rural banks to look into the special needs of small and mar-ginal farmers, landless workers, rural artisans and the rural poor in general.

5. The Government:

The Government has also provided short-term and long-term loans to farmers in times of emergency such as floods or famine. Such loans are known as Taccavi loans.

E - निम्नलिखित योजनाओं पर टिप्पणी कीजिए।

A. मुद्रा बैंक योजना :–

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की शुरूआत 8 अप्रैल 2015 को की।
– उद्देश्य :– छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढावा देना है।
– इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटर प्रेन्योर्स को 10 लाख रूपये तक का क्रेडिट देती है और माइक्रो फाइनेंस

E- Comment on the following schemes.

A- Mudra Bank Yojna

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) is a flagship scheme of Government of India to "fund the unfunded" by bringing such enterprises to the formal financial system and extending affordable credit to them. It enables a small borrower to borrow from all Public Sector Banks such as PSU Banks, Regional Rural Banks and Cooperative Banks, Private Sector

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

इंस्टिट्यूसंश के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है।

– इसमें–शिशु में 50 हजार तक का लोन, किशोर में 50 हजार से 5 लाख तक का और तरूण में 5 लाख से 10 लाख तक, का लोन दिया जाता है।

B. किसान विकास पत्र :–

– यह एक सर्टिफिकेट योजना है, पहलीबार 1988 में लान्च की गई तथा अभी 2014 में दुबारा से प्रारम्भ किया गया।

– वित्तमंत्री अरूण जेटली ने 18 नवम्बर 2014 को लॉन्च किया।

– इसमें 1 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 50 हजार की राशि को 100 महीनों में दुगुना करने का प्रावधान है।

– इसमें किसान व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता हैं, जिसका प्रयोग कर्ज या ऋण लेने में किया जा सकता है।

F- खाद्य प्रसंस्करण का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्या भूमिका है। स्पष्ट कीजिए।

खाद्य प्रसंस्करण :– मानव या प्रशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को अन्य रूपों में बदलने की तकनीक है जैसे डेयरी उत्पाद भोजन, पेयपदार्थ आदि। इससे उत्पादन, वृद्धि, खपत निर्यात में भारत के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे सरकार द्वारा प्राथमिक दर्जा प्राप्त है।

अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका :–

– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रत्यक्षर एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के नए अवसर सृजन करता है।

– इससे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले प्रवसन को कम किया जा सकता है।

– यह फसल विविधीकरण में भी सहायक है फल,सब्जियाँ, दुध इत्यादि के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करता है जिससे आय में वृद्धि होगी।

– प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के निर्यात से, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है।

– एसोचैम की रिपोर्ट से वर्ष 2024 तक भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 33 अरब डॉलर का निवेश और 90 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

– इस उद्योग को बढावा देने के लिए मेगा कूड पार्क योजना शुरू की गई।

उपर्युक्त बिन्दुओं से ज्ञात होता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वर्तमान एवं भावी रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

Banks, Foreign Banks, Micro Finance Institutions (MFI) and Non Banking Finance Companies (NBFC) for loans upto Rs 10 lakhs for non-farm income generating activities. The scheme was launched on 8th April, 2015 by the Hon'ble Prime Minister.

B- Kisan Vikas Patra

India Post introduced the Kisan Vikas Patra as a small saving certificate scheme in 1988. Its primary objective is to encourage long-term financial discipline in people. As per the 2014 amendment of the scheme, the tenure for the scheme is now 118 months. The minimum investment is Rs. 1000 and there is no upper limit. And if you invest a lump sum today, you can get double the amount at the end of the 118th month. Initially, it was meant for farmers to enable them to save for long-term, and hence the name. Now it is available for all

F- What is the role of Food Processing in the development of the Indian economy ? Elaborate it.

Food processing industry is of enormous significance for India's development because of the vital linkages and synergies that it promotes between the two pillars of our economy, industry and agriculture. Fast growth in the food processing sector and simultaneous improvement in the development of value chain are also of great importance to achieve favorable terms of trade for Indian agriculture both in the domestic and the international markets.

Importance of Food Processing Industry

1. It holds the potential of reducing enormous wastage of agricultural produce in the absence of processing technologies and cold chain facility
2. It is labour-intensive industry, which has the potential to employ 13 million people directly and 35 million people indirectly
3. This will also lead to an increase in farm income, generate employment opportunities, foster forward and backward linkage effects, contribute to exports and integrate Indian economy with the rest of the world.

India Food Processing Industry is estimated at $135 billion industry which is growing at about 8% annually. This growth rate is significantly more than agricultural growth rate which remains around 4%.

India's food processing sector ranks fifth in the world in exports, production and consumption.

Importance of this sector is significant and it deserves a priority treatment by government.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

G- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा कीजिए।

भातर में गरीबों के लिए सब्सिडी और गैर खाद्य वस्तुओं का वितरण करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व का सबसे बडा खाद्य सुरक्षा नेटवर्क माना जाता है।

प्रणाली की समीक्षा :– विश्व बैंक के अनुसार भारत की लगभग 80% आबादी प्रतिदिन आय से कम पर जीवन व्यतीत करती है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खाद्य सब्सिडी का भार बढ गया है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने में समस्या।
- उचित मूल्य की दुकानों से अनाज का रिसाव होना।
- कई राज्यों में FCI द्वारा निर्गत मूल्य एवं बाजार मूल्य में निम्न अन्तर का होना।
- PDS का वस्तु ढाँचा गरीबों के पक्ष में नही है चीनी, गेहूँ तेल का भाग 86% है जबकि मोटे अनाज का कुल, वितरण 1% है जो गरीब वर्ग द्वारा उपभोग किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कई रूप से असफल रही है, वास्तविक गरीबों तक पहुँचने में असफल रही है। इसके बाबजूद भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, गरीबी निवारण का एक सशम्त माध्यम भी है।

H- मेगा फूड पार्क स्कीम से क्या समझते है ? एवं इसके उद्देश्यों की व्याख्या करें।

मेगा कूड पार्क – किसानों से खाद्य एंव कृषि उत्पादों को कृय करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध करवाते है तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते है।

मेगा कूड पार्क योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई।

उद्देश्य :–

- किसानों प्रसंस्करणकर्ता तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना।
- कृषि उत्पादकता को बाजार से जोडने के लिये एक तंत्र उपलब्ध कराना
- मूल्यवर्द्धन को अधिकतम बनाना, फसल बर्बादी को न्यूनतम करना।
- कृषि/बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराना।

G- Review the Public Distribution System.

The Public Distribution System (PDS) evolved as a system for distribution of foodgrains at affordable prices and management of emergency situations. Over the years, the term PDS has become synonymous with the term 'food security' and also an important part of Government's policy for the management of food economy in the country.

The central and state governments shared the accountability of regulating the Public distribution system.

The objectives of the Public Distribution System are as follows:

1. To protect the low income groups by guaranteeing the supply of certain minimum quantities of food grains at affordable price.
2. Ensuring equitable distribution.
3. Controlling the price rise of Essential Commodities in the open market.

Flaws of public distribution system-

1. Limited Benefit to Poor from PDS.
2. Regional Disparities in PDS Benefits.
3. The Question of Urban Bias. A number of economists have pointed out that PDS remained limited mostly to urban areas for a considerable period of planning while the coverage of rural areas was very insufficient.
4. The Burden of Food Subsidy. PDS is highly subsidised in India and this has put a severe fiscal burden on the government.
5. Corruption in public distribution system.

H- What do you understand by MEGA Food Park Scheme . Explain its purposes.

Mega Food Park is a scheme of the Ministry of Food Processing (part of the Government of India) with the aim of establishing a "direct linkage from farm to processing and then to consumer markets" through a network of collection centres and primary processing centres.

Its purpose was to increase processing of perishables from 6% to 20% and to increase India's share in global food trade by at least 3% up to the year 2015.

Highlights of scheme -

- Government provides grants up to Rs 50 crores for each food park to a consortium of companies.
- 30-35 food processing units are expected to be established.
- Collective investment of companies is expected to be at least 250 crores.

Purpose of Mega Food Parks

1. Cluster Based Approach

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।

I - मध्यप्रदेश में परिवहन के विकास में कौनसी समस्याएं व्याप्त है ?

– मध्यप्रदेश में परिवहन विकास की समस्याएँ

मध्यप्रदेश भारत में क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा राज्य है। मध यप्रदेश का क्षेत्रफल 308252 वर्ग किमी. है। इतने बड़े क्षेत्र में यातायात के साधनों का विकास करना कठिन कार्य है। यातायात विकास के मामले में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। मध्यप्रदेश में यातायात विकास गति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके लिए निम्न समस्याओं को चिन्हित किया जा सकता है–

– पूँजी की कमी।
– मध्यप्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति जैसे– समुद्री मार्गों का अभाव अर्थात् समुद्र से दूरी।
– मध्यप्रदेश की भौगोलिक संरचना जैसे–पठारों एवं बीहड़ों में परिवहन साधनों के विकास में कठिनाई एंव लागत वृद्धि।
– प्रशासनिक शिथिलता एवं भ्रष्टाचार।
– राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव।
– भूमि अधिग्रहण की समस्या। किसानों द्वारा आन्दोलन एवं विरोध।
– पर्यावरण समस्या एवं पर्यावरण मंजूरी मिलने में देरी।
– जनजातीय क्षेत्रों के विशेषाधिकारों के कारण उत्पन्न बाधाएँ।
– उच्चस्तरीय तकनीक का अभाव।
– कानूनी समस्याएँ।
– केन्द्र एवं राज्य सरकार में टकराव।
– सरकारी विभागों में समन्वय की कमी।
– जनभागीदारी का अभाव।
– परियोजनाओं का समय पर पूरा न होना जिससे लागत तो बढ़ती ही है साथ ही विकस की गति भी मंद पड़ जाती है।

2. Demand driven with a focus on strong backward and forward integration
3. Enabling Infrastructure Creation along the supply chain and technology
4. Creation of Central Processing Centre (CPC) and Primary Processing Centres (PPC)

I- What are the problems in the development of transport in Madhya Pradesh?

Good quality infrastructure is critical to sustainable growth, especially for rural areas. Investment in rural transport infrastructure stimulates the rural economy and hence acts as a tool for poverty reduction.

In the national scenario, transportation accounts for 8% of the GreenHouse Gases (GHGs) emissions in which road transport accounts for 94.5%. There is about 74,000 Km road network across the state in the form of national highways, state highways, district roads and village roads.

Problems in the development of transport in Madhya Pradesh -

1. The number of registered vehicles per thousand population of Madhya Pradesh is 80 as compared to the national level of 68, reflecting over dependency on privately owned vehicles in the absence of sufficient and efficient public transportation system.
2. Faulty Planning of Transport System:
The development of transport system is unbalanced. There is heavy pressure on rail and road transport in certain cities and regions.
3. Lack of RailRoad Coordination:
Rail and Road transport systems are the main means of transportation in a country. These two should work in coordination.
4. Worn out and Obsolete Assets:
The main problem of our transport system is its worn out and obsolete assets. In all modes of transport there are old and worn out infrastructure.
5. Geographical conditions such as long mountain range Of Satpura and Vindhyanchal also cause problems in providing transport facility to some remote villages.
6. MP has large forest cover. It is difficult to get environmental clearance for railway and roads construction in forest area.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

J - विमुद्रीकरण किसे कहते है ? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसको क्या प्रभाव पड़ता है ?

विमुद्रीकरण

जब किसी अर्थव्यवस्था में चलन में आई मुद्रा को बंद करके कोई (उसका Legal Tender रद्द करके) नई मुद्रा जारी कर दी जाये तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। यह मुख्यतः काले धन व जाली मुद्रा (Fake Currencey) को अर्थव्यवस्था से बाहर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारत में अब तक तीन बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है।

पहली बार जनवरी, 1946 में 1000, 5000 व 10000 के नोट बंद किये गये। पुनः जनवरी, 1978 को जनता पार्टी की सरकर द्वारा 1000, 5000 व 10000 के नोट बंद कर दिये। पुनः 8 नवम्बर, 2016 को 500 व 1000 रू. के नोट बंद करने की घोषणा की गई।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :–

सकारात्मक प्रभाव

- आयकर में वृद्धि।
- हवाला, जाली मुद्रा की चुनौती बुहत हद तक खत्म हो गई।
- मानव तस्करी (कबूतरबाजी) की समस्या कम हुई।
- आतंकवादियों, नक्सलवादियों, उग्रवादियों आदि के आर्थिक संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- आंतकवाद, अलगाववाद तथा नक्सलवाद फंडिग खत्म होने से इनकी गतिविधियाँ कम हुई।
- देश तेजी से कैशलेस सिस्टम की ओर बढ़ा जिससे पारदर्शिता बढ़ी।
- बैंकों में जमा राशि बढ़ने से कर्ज सस्ता हुआ।
- कुछ हद तक कालाबाजारी में गिरावट हुई।
- महंगाई कम हुई।
- जाली नोटों की समस्या एक झटके में लगभग समाप्त हो गई।
- बैंकिंग तंत्र को बड़ी मात्रा में नकदी की प्राप्ति हुई जिससे उसकी मौद्रिक तरलता में वृद्धि हुई।
- राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा मिला, जिससे वित्तीय तंत्र में पारदर्शिता आई।

नकारात्मक प्रभाव

- नकदी का गंभीर संकट
- संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को और अधिक संकटग्रस्त बनाया।
- विनिर्माण एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को हतोत्साहन
- असंगठित क्षेत्र में आपदा की स्थिति
- श्रम, भूमि व कर संबंधी आर्थिक सुधारों को अधर में लटका।
- आरबीआई, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली के प्रति देश के लोगों के विश्वास में कमी।

J- What is demonetization? What is the impact on the Indian economy ?

Demonetisation is a radical monetary step in which a currency unit is declared as an invalid legal tender. This is usually done whenever there is a change in the national currency of a nation. Such a step is especially taken to curb the menace of counterfeiting, black money and money laundering. A recent example is demonetisation of 500 and 1000 denomination currency units in India.

Impact of demonetisation -

1. Parallel economy- Demonetisation will curb the parallel economy as the owners of black money will not be in a position to deposit the money with them in the banks.
2. With the reduction in the consumption demand, GDP formation in the country could get adversely impacted. Demonetisation has led to a decrease of 1% in the country's GDP growth.
3. This move will increase the amount of money deposited in Savings and Current Account of commercial banks. Even most of the Jan Dhan accounts which were lying idle for months have seen some deposits.
4. There will be a surge in the online transactions and other modes of payment. E-wallets, digital transaction systems, e-banking, usage of plastic money are expected to see an increase in demand.
5. Demonetisation has reduced the RBI's profits. As a result, the government received a lesser dividend from the central bank.

Negative impact

- a serious financial crisis
- Make the distressed farm sector more endangered.
- Manufacturing and despatch of small and medium enterprises
- Disaster status in the unorganized sector
- Lack of economic reforms related to labor, land and tax.
- A lack of confidence in the people of the country towards RBI, currency and banking system.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

K- मध्यप्रदेश में पूंजी बाजार के समक्ष कौन–कौन सी चुनौतियां है?

मध्यप्रदेश में पूंजी बाजार काफी पुराना है। राज्य में 'मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज' इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1919 इंदौर में हुई। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।

मध्यप्रदेश में पूंजी बाजार के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां है–

– मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम कम्पनियाँ पंजीकृत है।
– मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज का सालाना कारोबार बहुत कम है।
– कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था व लोगों में शेयर बाजार में निवेश के प्रति अजागरूकता व रूचि कम होना।
– देश में दूसरे बड़े व ऑनलाईन शेयर बाजारों का विकल्प के रूप में होना।
– मध्यप्रदेश निवेश के हिसाब से अभी तक आकर्षक राज्यों में शामिल पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इस वजह से यहां का पूंजी बाजार पिछड़ा हुआ है।
– सरकार द्वारा पूंजी बाजार को आकर्षक करने के लिए 2007 से Global Invrestors Summit में किए गए समझौतों को प्रभावी तरीके से लागू ना कर पाना।
– MPSE Securities से संबंधित शिकायतें भी बहुत बड़ी है। विशेषकर NSE व BSE में इसके उपभोक्तओं की वजह से।
– मोद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, श्रम सुधार आदि में आर्थिक विकास को प्रभावित करने की शक्ति होती है। इससे पूंजी बाजार भी प्रभावित होता है।
– औद्योगिक पिछड़ापन होना।

K- What are the challenges before the Capital Market in Madhya Pradesh.

The capital market in Madhya Pradesh is quite old. In the state, 'Madhya Pradesh Stack Exchange' is playing an important role in this context. Madhya Pradesh Stack Exchange was established in Indore in 1919. This is India's third oldest stack exchange. The following challenges face the capital market in Madhya Pradesh:

- There are very few companies registered in the Madhya Pradesh Stock Exchange.
- The annual turnover of Madhya Pradesh Stack Excheases is very low.
- The lack of awareness and interest towards investment in the stock market in the agricultural economy and people.
- As an alternative to the second largest and online market share in the country.
- Madhya Pradesh has not been fully involved in attractive states according to investment. Because of this, the capital market here is backward.
- In order to make the capital market attractive by the government, it is not possible to implement the agreements executed in 2007 from the LSVN.
- Complaints related to Dammambant pajapam are also very big. Especially because of its consumers in Chham and Tham.
- There is power to influence economic development in monetary policy, fiscal policy, industrial policy, agricultural policy, labor reform etc. This also affects the capital market.
- Industrial backwardness

L- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम –2013, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक युगान्तकारी कदम है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना एवं उपयुक्त व्यवस्था करना।

आलोचना :–

– अधिनियम में गरीबों का निर्धारण कैसे किया जाएगा ? इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही है।
– जब तेंदुलकर/रंगराजा आदि कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने यह स्वीकारा है कि देश में 30–40 गरीब पाये है।

L- Critical evaluation of the National Food Security Act.

"There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread." The National Food Security Bill was passed by the parliament in 2013. As per the provisions of the Bill, it is proposed to provide 7 kg. of food grains per person per month belonging to priority households at prices not exceeding Rs. 3 per kg of rice, Rs. 2 per kg of wheat, and Rs. 1 per kg of coarse grains and to general households not less than 3 kg of food grains per person per month . It will benefit up to 75 per cent of rural population.

Priority households (under Antyodaya Anna Yojna) are entitled to get 35 kgs per household per month.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– अशोक गुलाटी ने तर्क दिया है कि अधिनियम के प्रावध ानों के अनुसार 250 लाख टन अनाज उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक हो जायेगी।
– खाद्य सुरक्षा को लेकर सबसे बडी समस्या PDS की खामियां एवं रिसाव है अधिनियम क्रियान्वयन के लिए पुनः PDS की ओर देखना पडता है।
– अधिनियम लागू करने पर सब्सिडि 1.30 लाख करोड रूपए तक पहुंच जाऐगी, जो कि राजकोषीय दबाव बनाते हुए छोटे घाटे को जन्म देगी।

For the children in the age bracket of 6 months to 6 years, the bill promise to get give age specific food, free of cost through the local Anganwadi.

The Act also has a special focus on the nutritional support to women and children. Besides meal to pregnant women and lactating mothers during pregnancy and six months after the child birth.

Challenges -

1. Food grains under the act will be distributed through the already existing PDS (Public Distribution System). But, these PDSs have many loopholes such as leakages of food grains, corruption etc.
2. The exact number of poor is not calculated correctly. Different departments are giving different numbers.
3. The cost of this bill, Rs.1.24 lakh crore will be a burden for the government, and may lead to fiscal deficit.
4. As most of the food grains will be procured by Govt, exports will be reduced, which is a big threat to the economy.
5. Small farmers may shift to other crops, as they may get the subsidized food grains. This may reduce the production of food grains.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

PART- B15 Marks

A- बफर स्टॉक क्या है ? बफर स्टॉक के लाभ एवं हानियां बताइए।

बफर स्टॉक एक ऐसी व्यसस्था है जिसके अंतर्गत मूल्यों में उतार–चढाव से बचने के लिये और आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। बफर स्टॉक व्यवस्था के अंतर्गत अच्छे उत्पादन की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों का क्रय कर उनका संग्रह कर लिया जाता है ताकि अधिक उत्पादन की स्थिति में बाजार में उनकी कीमतो को निध र्ारित मूल्य स्तर से कम होने से रोका जा सके एवं इसी प्रकार कम उत्पादन की स्थिति में इस बफर स्टॉक अर्थात् भंडारित खाद्यान्नों को निर्गमित करके बाजार में उनकी कीमतों को निर्धारित मूल्य स्तर से अधिक होने से रोका जा सके।

बफर स्टॉक की अवधारणा की शुरूआत चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) के दौरान की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिये आवश्यक खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिये भारत सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम आवश्यक बफर स्टॉक को बनाए रखता है, बफर स्टॉक संबंधित मानकों का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूम्बर और 1 जनवरी को त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। परिचालन स्टॉक के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये निर्धारित बफर स्टॉक और सरकार की कल्याणकारी योजनओं के लिये आवश्यक खाद्यान्नों का स्टॉक रखा जाता है।

बफर स्टॉक के लाभ

- प्राकृतिक आपदाओ एवं खराब फसल की स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- खुले बाजार में खाद्यान्नों की मांग एवं पूर्ति को संतुलित करके खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर बनाए रखना;
- खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन होने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका क्रय करके किसनों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना;
- खाद्यान्नों के कम उत्पादन होने की स्थिति में उनका निर्गमन कर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कर उनके हितों की रक्षा करना;
- खाद्यान्नों के संदर्भ में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना।

बफर स्टॉक की हानियाँ

A- What is buffer stocks?
Explain the advantages and disadvantages of buffer stocks.

A buffer stock scheme is an attempt to use commodity storage for the purposes of stabilising prices in an entire economy or an individual (commodity) market.Specifically, commodities are bought when a surplus exists in the economy, stored, and are then sold from these stores when economic shortages in the economy occur.

Advantages of a successful buffer-stock scheme:

1. Stable prices help maintain farmers' incomes and improve the incentive to grow legal crops
2. Stability enables capital investment in agriculture needed to lift agricultural productivity
3. Farming has positive externalities it helps to sustain rural communities
4. Stable prices prevent excess prices for consumers – helping consumer welfare.

Problems with buffer stock schemes

In theory buffer stock schemes should be profit making, since they buy up stocks of the product when the price is low and sell them onto the market when the price is high. However, they do not often work well in practice.

Clearly, perishable items cannot be stored for long periods of time and can therefore be immediately ruled out of buffer stock schemes. Other problems are:

1. Cost of buying excess supply can cause a buffer stock scheme to run out of cash
2. A guaranteed minimum price might cause overproduction and rising surpluses which has economic and environmental costs
3. Setting up a buffer stock scheme also requires a significant amount of start up capital, since money is needed to buy up the product when prices are low.
4. There are also high administrative and storage costs to be considered.

The success of a buffer stock scheme however ultimately depends on the ability of those managing a scheme to correctly estimate the average price of the product over a period of time.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– अधिक उत्पादन की स्थिति में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक खाद्यान्न खरीदने से सरकार की भंडारण लागत बढ जाती है एवं रख–रखाव के व्ययों में भी वृद्धि होती है।
– बफर स्टॉक को बनाए रखने पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो सकती है जिससे वहाँ खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
– बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिये काफी धनराशि खर्च की जाती है। जिससे प्रशासनिक लागतों में भी काफी ज्यादा वृद्धि होती है।
– सामन्यतया भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण क्षमता से अधिक का अनाज क्रय कर लिया जाता है और उपयुक्त भंडारगृहों के न होने से खाद्यान्नों की बर्बादी होती है। बफर स्टॉक के लिये स्पष्ट लक्ष्यों के अभाव में भारतीय खाद्य निगम की बफर स्टॉक प्रणाली अप्रभावी और महँगी हो जाती है।

B - वित्तीय समावेशन को समझाते हुए इसके लिए पूर्व में एवं वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करें ?

वित्तीय समावेशन' का अर्थ है– बैंकिंग एवं वित्तीय सुविध ाओ को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाना। वित्तीय समावेशन को हमारे देश में प्रायः बैंक खातों तक पहुँच के रूप में देखा जाता है, कि जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं, जैस–पेंशन, बीमा व पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। कम आय व कमजोर वर्ग के लिये ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुँच ही वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन में बैंकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक वित्तीय समावेशन की मुहिम में ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी देकर, बैंकिंग सेवाओं के सही एवं उचित उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर, बचत के लिये प्रोत्साहित कर सकते है। इसके साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को धन प्रबंधन और ऋण संबंधी सलाह देकर तथा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर सहयोग कर सकते है। वित्तीय समावेशन ग्रामीणों की बचत को बैकों के माध्यम से इकट्ठा कर उन्हें उचित आय प्राप्ति एवं सुरक्षा प्रदान करेगा तथा बचत की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार वित्तीय समोवशन किसी–न–किसी रूप में समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा करता है।

B- Explaining the financial inclusion, mention the efforts being made in the past and present for this.

Financial Inclusion is described as the method of offering banking and financial solutions and services to every individual in the society without any form of discrimination. It primarily aims to include everybody in the society by giving them basic financial services without looking at a person's income or savings. Financial inclusion chiefly focuses on providing reliable financial solutions to the economically underprivileged sections of the society without having any unfair treatment. It intends to provide financial solutions without any signs of inequality. It is also committed to being transparent while offering financial assistance without any hidden transactions or costs .

Financial Inclusion Schemes in India -

The Government of India has been introducing several exclusive schemes for the purpose of financial inclusion. These schemes intend to provide social security to the less fortunate sections of the society. After a lot of planning and research by several financial experts and policymakers, the government launched schemes keeping financial inclusion in mind. These schemes have been launched over different years. • Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

- Atal Pension Yojana (APY)
- Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
- Stand Up India Scheme
- Pradhan Mantri Mudra Yojana

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में कई बाधाएँ हैं, जैसे–

– आज भी भारत के ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र में बैंकों की शाखाएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं खोली गई है।
– निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम शाखाएँ खोली गई है।
– ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्रों में बैंक की बुनियादी एवं ढाँचागत सुविधओं की आज भी कमी है।
– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं अशिक्षा के चलते लोक कर्ज लेकर कुछ व्यापार या स्वरोजगार तो चला सकते है, किन्तु बचत की कमी के चलते वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते है।
– ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आज भी बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं होती है।

भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिये आजादी के बाद से ही जो प्रयास किये है, वे है–

पूर्ववर्ती पहलें :–

– ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिये ऋण तथा बचत सुविधाएँ प्रदान करने वाले सहकारी बैंकों का विस्तार;
– निजी क्षेत्र के बैंकों का 1969 एवं 1980 में राष्ट्रीयकरण;
– बैंकिंग शाखाओं का विस्तार;
– प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विस्तृत ढाँचे का सृजन;
– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) की स्थापना तथा इनका शाखा विस्तार;
– NABARD की स्थापना;
– विभेदीकृत ब्याज दर योजना।

हाल ही में की गई पहलें

– No-Frills Account अर्थात् जीरो बैंलेंस अकाउंट;
– सरलीकृत KYC (Know Your Customer- अपने ग्राहक को जानो);
– ऋण परामर्श सेवा केन्द्रों का विस्तार;
– गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) का उपयोग व स्वयं सहायता समूह (SHGs) का गठन;
– किसान क्रेडिट कार्ड;
– स्मार्ट काड्र्स का विस्तार;
– मोबाइल फोन बैंकिंग जैसी प्रौद्योगिकी का विस्तार;
– नीतिगत पहल के रूप में वित्तीय शिक्षा को बढवा देना;
– माइक्रो फाइनेंस का विस्तार;
– नए वित्तीय उत्पादों का सृजनः
– इंटरनेट बैंकिंग सुविधा;
– स्वाभिमान योजना;
– प्रधानमंत्री जन–धन योजना।

- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) • Sukanya Samriddhi Yojana
- Jeevan Suraksha Bandhan Yojana
- Credit Enhancement Guarantee Scheme (CEGS) for Scheduled Castes (SCs)
- Venture Capital Fund for Scheduled Castes under the Social Sector Initiatives
- Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY)

Objectives of Financial Inclusion

- Financial inclusion intends to help people secure financial services and products at economical prices such as deposits, fund transfer services, loans, insurance, payment services, etc.
- It aims to establish proper financial institutions to cater to the needs of the poor people.
- Financial inclusion aims to build and maintain financial sustainability so that the less fortunate people have a certainty of funds which they struggle to have.

There are many governmental agencies and non-governmental organisations dedicated to bringing in financial inclusion.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY
INDORE

C - जीएसटी का स्वरूप क्या है तथा जीएसटी परिषद के कार्यो की विवेचना कीजिए ?

भारत एक संघीय 'राज्य' है, जहाँ केंन्द्र और राज्यों को उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और करों को एकत्र करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। यह कर केन्द्र और राज्यों के द्वारा एक साथ, सामान्य कर आधार पर अरोपित दोहरा कर है। कर का प्रशासन केंन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। यह कर केंन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। एक राज्य के भीतर होने वाले लेन–देन पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाता है एवं सीजीएसटी केंन्द्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। राज्यों द्वारा लगाए करों को राज्य जीएसअी (एसजीएसटी) कहा गया है और एसजीएसटी संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाता है। इसी प्रकार केंन्द्र द्वारा प्रत्येक अंतर–राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ती पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाने और प्रशासित करने की व्यवस्था है।

जीएसटी परिषद् के कार्य

जीएसटी परिषद् का कार्य निम्नलिखित विषयों पर केंन्द्र और राज्यों की सिफारिश करना है–

- केंन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर और अधिशुल्क जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया जा सके;
- ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ, जिन्हें जीएसटी के अधीन या उससे छुट प्रदान की जा सकती है।
- वह तारीख, जब से कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी वसूला जा सकें;
- आदर्श जीएसटी कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत, आईजीएसटी का बँटवारा और आपूर्ति के स्थान को प्रशासित करने वाले सिंद्धात;
- वह सीमा रेखा, जिसके नीचे वस्तु एवं सेवा के टर्नओवर को जीएसटी से छूट प्रदान की जा सके;
- किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने हेतु किसी विशेष अवधि के लिये कोई विशेष दर या दरें;
- उत्तर–पूर्वी एवं पर्वतीय राज्यों–अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधानः

C- What is the nature of GST and please consider the functions of the GST Council.

GST is an Indirect Tax which has replaced many Indirect Taxes in India. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017.

In simple words, Goods and Service Tax (GST) is an indirect tax levied on the supply of goods and services. This law has replaced many indirect tax laws that previously existed in India.

The Goods & Services Tax Council {GST Council} has been created in September 2016 under Article 279-A of the Constitution of India. The main objective of GST is to develop a harmonized national market of goods and services. It has its Secretariat office in New Delhi.

Composition of GST Council

GST Council is a federal forum with both centre and states in India on board. It is made of:

- The Union Finance Minister (as Chairman),
- The Union Minister of State in charge of Revenue or Finance, and
- The Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister, nominated by each state government.

Functions of GST Council

As per Article 279A (4), the Council will make recommendations to the Union and the States on important issues related to GST, like

1. Taxes, cesses, and surcharges to be subsumed under the GST;
2. Goods and services which may be subject to, or exempt from GST;
3. The threshold limit of turnover for application of GST;
4. Rates of GST;
5. Model GST laws, principles of levy, apportionment of IGST and principles related to place of supply;
6. Special provisions with respect to the eight north eastern states, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Uttarakhand; and

Other related matters.

GST rates will include the floor rates with bands, special rates for raising additional resources during natural disasters / calamities, special provisions for certain States, etc.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– जीएसटी परिषद् द्वारा यथा निर्णय एवं जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला, जिस पर परिषद् निर्णय ले सकती है।

D - भारत में आधारभूत अधोसंरचना पर लेख लिखिए ?

वह सभी क्रियायें व सुविधायें जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास एवं प्रगति में सहायक होती है। आधार–भूत अधोसंरचना कहलाती है। जैसेः– ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विकासशील देश में अधोसंरचना का निर्माण व विकास महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

1. **ऊर्जा या शक्ति के साधन :–** किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में ऊर्जा के साधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत मानव विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। भारत में ऊर्जा के साधन मुख्यतः परम्परागत (कोयला, पेट्रोलियम) है वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए गैर परम्परागत स्त्रोत (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि) का विकास भी किया गया है।
2. **परिवहन/यातायात के साधनः–** यातायात के साधन किसी देश के विकास व संचालन में महत्वपूर्ण व अपरिहार्य भूमिका निभाते है। भारत में परिवहन आधुनिक साधनों–सड़कें, रेलवे, वायु व जल परिवहन आदि निरंतर विकासमान अवस्था में है।
3. **संचार :–** वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संचार साधनों की उपलब्धता देश व समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेलीफोन, मोबाईल, इंटरनेट, सोशल साईट्स, डाक, फैक्स, ई–मेल, संचार उपग्रह आदि आधुनिक संचार के साधन हैं।

   देश में टेली घनत्व मार्च, 2018 की स्थिति में 93.23 प्रतिशत था।
4. **शिक्षा :–** व्यक्ति में समाज व अपने वातावरण के प्रति समझ बढ़ाकर विकास को आसान बनाने में शिक्षा प्रभावी कारक होता है। भारत में जनगणना, 2011 के अनुसार, 73 प्रतिशत साक्षरता हैं इसमें पुरूष साक्षरता 82 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 65 प्रतिशत है।

   लोगों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का विकास करने के साथ ही उनके कौशल वृद्धि, कार्य कलापों में

D- Write an article on basic infrastructure in India.

Infrastructure is a key driver of the overall development of Indian economy. Infrastructure sector focuses on major infrastructure sectors such as power, roads and bridges, dams and urban infrastructure.

"Infrastructure is generally understood as the basic building blocks required for an economy to function efficiently."

The World Bank treats power, water supply, sewerage, communication, roads & bridges, ports, airports, railways, housing, urban services, oil/ gas production and mining sectors as infrastructure.

Infrastructure development plays a very significant role in its economic growth of a nation. Taking examples from other countries, a fast growing economy drive demand and lead to an even faster development of infrastructure. However, India's case is a bit disappointing, which currently ranked 91st out of 139 nations in quality of infrastructure according to the IMF, though India has always been quoted as the country with the highest growth potential after China. The worst is low quality infrastructure system becomes an obstacles presenting India from breaking into the world of developed nations and bringing the citizens out of poverty. The following will summarize the reason for this underperformance and discuss the potential and treat along the path of development.

Numerous problems now causing the failure of India's infrastructure are land clearance issues; insufficient compensation, unclear regulations, access to financing etc.

Nevertheless, Indian Government did have a strong will in growing infrastructure. Structural and procedural reforms at various government levels have been taken place to facilitate infrastructure growth. Apart from local private capital and return from public user fees, Indian Government acknowledge that foreign investment is a major source of investment into the infrastructure sector, therefore she is providing more flexibility towards capital flow and is setting policy to lower the risk and increase private capital return.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

दक्षता, प्रशासन के संचालन हेतु अनेक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं।

5. **स्वास्थ्य :–** लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य व सबल बनाकर कुशल मानव संसाधन के विकास हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। सहायता, महिलाओं, बच्चों, वंचित समूहों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अनेक योजनाएं व कार्यक्रम संचालित है।
6. **आवास :–** देश में शहरों व ग्रामों में निरंतर रहवासों को निर्मित व उन्नत किया जा रहा है। गरीब व वंचित वर्गों को मुफ्त या रियायती दरों पर घर उपलब्ध करवाये जा रहे है। राष्ट्रीय आवास मिशन (2008), इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना आदि कार्यक्रम संचालित हैं।
7. **जलापूर्ति :–** पीने हेतु स्वच्छ पेयजल तथा कृषि व उद्योगों में उपयोगी जल के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय जल मिशन, नल–जल योजनाएं, बड़े व छोटे बांध, खेल तालाब योजना, बलराम ताल योजना आदि से जलपूर्ति की सुविधाएं विकसित हुई।
8. **साफ–सफाई :–** घर व शहरों तथा गांवों के साफ–सफाई का ढांचा विकसित किया जा रहा हैं। स्वच्छ भारत अभियान, मलिन बस्ती विकास, एनआरएच एम आदि के द्वारा देश में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इनके अलावा सीमेंट, इस्पात, उपभोक्ता उद्योग, बांध, पुल नहरें आदि की उपलब्धता भी देश में अन्य क्षेत्रों के विकास को गति मिली है ओर देश व समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं।

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE